जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

# राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 50 संख्याः 100 प्रभात कोटा, बुधवार 22 जनवरी, 2025 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 2.50 रु.

## अमेरिका को औद्योगिक उत्पादन का केन्द्र बनाना, कर्णप्रिय नारा ही रह जायेगा?

### क्या अमेरिका अपने इन्फ्रास्ट्रक्चर, परिवहन, ऊर्जा, डिजिटल नैटवर्क में इतना पैसा लगा सकेगा, जिससे अमेरिका में औद्योगिक गतिविधि बढ़ाने (काम करना) का खर्चा, चीन में काम करने के खर्चे की तुलना में महंगा न हो।

- ऑपरेटिंग कॉस्ट कम करने के लिये शिक्षा व स्किल डवलपमैंट में भारी तब्दीली की जरूरत होगी।
- चीन में निर्मित वस्तुओं पर भारी टैक्स से चीन व अमेरिका में प्रतिस्पर्धा व दूरी बढ़ेगी तथा अन्य देशों को किसी न किसी की तरफ झुकना होगा, जिससे विश्व में तनाव बढ़ेगा।
- ट्रम्प की नीतियों के कारण विश्व की वर्तमान व्यवस्था (ग्लोबल ऑर्डर) बदलेगी तथा अमेरिका की अन्य देशों के साथ में लेकर, उनके साथ मंथन करके नीति निर्धारण करने की आदत नहीं है और यह आदत मजबूत होगी, जिससे ध्रुवीकरण बढ़ेगा।
- इससे कुछ देशों को थोड़ा लाभ हो सकता है, पर, अधिकतर देशों को इस इकोनॉमिक भूचाल का सामना करने में काफी कष्ट होगा।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 फरवरी। अपनी बात को सच सिद्ध करते हुये, डॉनल्ड ट्रम्प सोमवार को फिर से अमेरिकन राष्ट्रपति बन गये हैं, भले ही वहाँ के तमाम सन्तुलन बिगड़ गये हों। उन्होंने अपने उद्घाटन भाषण में संरक्षणवाद, अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग के पुनरोद्धार तथा "अमेरिकन फर्स्ट" की नीतियों पर जोर दिया था। उनका यह भाषण रुढ़िवादी अमेरिकनों तथा उन लोगों को बहुत प्रिय लगा होगा, जिन्होंने उन्हें पतनोन्मुखी अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिये उन्हें विशाल जनादेश दिया है।

ट्रम्प की भाव-भंगिमा नीतियों के मामले में शेष विश्व को उनके अनुकूल होना आवश्यक कर देगी। अनिश्चितता के इस दौर में अन्य राष्ट्र स्थिरता और ग्रोथ बनाये रखने के लिये अपनी नीतियों में आंशिक बदलाव के लिये मजबूर हो जायेंगे।

घरेलू निर्माण को प्राथमिकता देना एवं आयातों पर निर्भरता कम रखने को प्राथमिकता देने का ट्रम्प का वादा व्यापार में अवरोधों के फिर से उभरने, जिनमें टैक्स और कड़ी व्यापारिक नीतियाँ शामिल हैं, का संकेत दे रहा है। यह चीज वैश्वीकरण को अलविदा कहने का प्रतीक है तथा इससे लम्बे समय से स्थापित ट्रेड-पैटर्न अवरुद्ध होंगे तथा वैश्विक बाजार में अनिश्चितता पैदा होगी।

जहाँ तक अमेरिका को अग्रणी मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की आकांक्षा का प्रश्न है, यह एक महत्वाकांक्षा है तथा इसमें बहुत बाधाएं आयेंगी। अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर उन्नत उद्योगों की दिशा में बढ़ चुका है, जिसके लिये अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता है। चीन, जिसे कॉस्ट एफिशिएंसी के लिये जाना जाता है, जैसे देशों की प्रतियोगिता में, नवाचार और स्वचालित मशीनों की जरुरत होगी,

( शेष पृष्ठ 3 पर )

## पूरे देश में 26 जनवरी को किसान ट्रैक्टर मार्च

सिरसा, 21 जनवरी। सयुंक किसान मोर्चा ( एसकेएम) गैर-राजनीतिक, केएमएम व जगजीत सिंह डल्लेवाल के आव्हान पर 26 जनवरी को पूरे देश में किसान ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे, जिसके लिए पांच पॉइंट दिए गए हैं। साईलोज, टोल प्लाजा, भाजपा मुख्यालय, एमपी, एमएलए, मंत्रियों के घर, शॉपिंग मॉल व राष्ट्रीय व राज्यमार्ग पर दोपहर 12 बजे से लेकर 1.30 बजे तक पूरे देश के किसानों का ट्रैक्टर सड़कों पर होगा।

इसी कड़ी में सिरसा जिले में भी

- संयुक्त किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष लखविन्दर सिंह ने घोषणा की।

कई पॉइंट बनाए गए हैं, जिसमें भावदीन टोल प्लाजा, खुईया टोल प्लाजा, ओढ़ां से पन्नीवाला, साहुवाला, खारिया, सादेवाला, बनी, दमदमा, पोहड़का, चोपटा, रोड़ी से फग्गू सहित कई जगहों पर 26 जनवरी को दोपहर 12 बजे से 1.30 बजे तक किसान अपने ट्रैक्टरों से मार्च निकालेंगे।

उक्त जानकारी बीकेई प्रदेशाध्यक्ष लखविंदर सिंह ने मंगलवार को मीडिया को दी। उन्होंने बताया कि पिछले 344 दिनों से खनौरी, शंभू व रतनपुर बॉर्डरों पर एसपी खरीद गारंटी कानून व किसानों, मजदूरों की कर्ज माफी सहित 12 मांगों को लेकर किसान आंदोलन-2 चल रहा है।

पंजाब-हरियाणा के खनौरी बॉर्डर पर किसान नेता जगजीत सिंह

( शेष पृष्ठ 3 पर )

## 'ब्रिक्स देश "डॉलर" से दूरी बनायें और हम देखते रहें?'

### ट्रम्प ने पद संभालते ही ब्रिक्स देशों को चेतावनी दी और कहा कि विश्व व्यापार में डॉलर के महत्व को घटाने का प्रयास हुआ तो अमेरिका ब्रिक्स देशों पर सौ प्रतिशत शुल्क लगायेगा

- धमकी की फुसफुसाहट होते ही भारत ने इस मुद्दे पर समझौते की बात करनी शुरु कर दी।
- विदेश मंत्री जयशंकर ने दोहा में कहा, भारत का कोई इरादा नहीं है, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में डॉलर का महत्व कम करने का। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा "ट्रेड पार्टनर" है और हमारा डॉलर के महत्व को कम करने का कतई इरादा नहीं है।
- जैसा कि विदित ही है, अन्तर्राष्ट्रीय डॉलर का हिस्सा, जो 1999 में 71 प्रतिशत था, अब 2024 के मध्य में घट कर 58 प्रतिशत रह गया है।

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 फरवरी। पदभार ग्रहण करने के शीघ्र बाद, प्रैसिडैंट डॉनल्ड ट्रंप ने ब्रिक्स देशों, जिनमें भारत भी शामिल है, पर सौ प्रतिशत टैरिफ (शुल्क) लगाने का सुझाव दिया। ट्रंप का दावा है कि यह कदम वॉशिंगटन और दिल्ली के बीच व्यापारिक समीकरण को नया रुप दे सकता है।

ओवल ऑफिस से कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर करते हुए ट्रंप ने कहा, "एक ब्रिक्स देश के रुप में अगर वे उस योजना को लागू करने के बारे में सोचते भी हैं, तो उन्हें सौ प्रतिशत टैरिफ का सामना करना पड़ेगा। वे इसे तुरंत छोड़ देंगे।" उनके बयान का संकेत ब्रिक्स देशों की, वैश्विक व्यापार में अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता को कम करने की सोच की तरफ था। ट्रंप ने स्पष्ट किया कि उनका बयान एक दृढ़ रुख है, न कि धमकी।

शपथ ग्रहण से पहले, ट्रंप ने दिसम्बर 2024 में ही चेतावनी दे दी थी कि वे ऐसे शुल्क लागू करेंगे, जब तक ब्रिक्स देश यह वचन नहीं देते कि वे अमेरिकी डॉलर का विकल्प नहीं बनाएंगे। अपने "ट्रुथ सोशल" प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कहा, "ब्रिक्स देश डॉलर से दूर जाएं और हम देखते रहें, अब ऐसा नहीं होगा।"

भारत के विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने दिसम्बर 2024 के दोहा फोरम में प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा था कि अमेरिकी डॉलर को कमजोर करने में भारत की रुचि नहीं है। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान भारत के उनके साथ मजबूत संबंधों का हवाला देते हुए जयशंकर ने कहा, "प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच व्यक्तिगत कनैक्शन है। भारत डॉलर-निर्भरता को कम करने की कोशिश नहीं कर रहा है, और ब्रिक्स की अपनी अलग मुद्रा का कोई प्रस्ताव नहीं है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, और डॉलर को कमजोर करने का कोई कारण नहीं है।"

ब्रिक्स, जो दस देशों- भारत, रुस, चीन, ब्राज़ील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, इथियोपिया, ईरान, इंडोनेशिया, और यूएई का एक गठबंधन है, अमेरिकी डॉलर के विकल्प की तलाश करता रहा है। यह प्रयास 2022 में रुस पर अमेरिकी नेतृत्व वाले प्रतिबंधों के बाद और अधिक मजबूत हुआ। रुस डॉलर-निर्भरता को कम करने का मुखर समर्थक रहा है और इसे पश्चिमी-प्रभुत्व वाले वित्तीय सिस्टम से दूर रहने की रणनीति के रुप में देखता है।

( शेष पृष्ठ 3 पर )

## एआईसीसी में काम-काज लगभग ठप्प है, फेरबदल के इंतजार में

### कई पदाधिकारी पूर्णतया अस्वस्थ हैं, कई "अच्छी" जिम्मेवारी की चाह में कई बार वर्तमान पद छोड़ने की प्रबल इच्छा जाहिर कर चुके हैं, पर, संभावित व बहुप्रतीक्षित फेरबदल केवल चर्चाओं तक ही सीमित है

- के.सी. वेणुगोपाल, सुरजेवाला, सुखविन्दर सिंह रंधावा, हरियाणा प्रभारी बाबरिया, देवेन्द्र यादव, भँवर जितेन्द्र सिंह, अविनाश पाण्डेय, उस लिस्ट में प्रमुख हैं, जिनको पद मुक्ति की पुरानी आशा है। पर, फिलहाल, फेरबदल होता नज़र नहीं आ रहा, क्या ऐसे में नरेन्द्र मोदी की भाजपा को हराने की तैयारी हो रही है, कांग्रेस में।

- रेणु मित्तल -
- राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो -

नई दिल्ली, 21 जनवरी। इस समय एआईसीसी में काम-काज वस्तुतः रुक-सा गया है, क्योंकि अत्यधिक सीनियर तथा उनसे कुछ कम सीनियर नेतागण एआईसीसी में लम्बे समय से चर्चित और सोची-समझी फेरबदल होने की प्रतीक्षा कर रहे हैं।

लेकिन अभी तक तो केवल सुगबुगाहट एवं अपेक्षाएं ही अस्तित्व में है, उस दिशा में किसी प्रकार की जमीनी हलचल या गतिविधि दिखाई नहीं दे रही है।

एक पार्टी पदाधिकारी ने कहा कि बदलाव तो काफी लम्बे समय से लम्बित हैं, लेकिन अब तक ऐसा प्रतीत नहीं हुआ है कि इस मामले में कोई गंभीर कवायद हुई है या हो रही है।

ऐसे नेता, जो काफी अस्वस्थ हैं तथा अपना काम करने की स्थिति में नहीं हैं, आज भी अपने पदों पर बने हुये हैं।

बाबरिया, जो अस्पताल में भर्ती थे, आज भी हरियाणा के प्रभारी हैं, जबकि उन्हें दिल्ली का प्रभार भी संभालना है, जिसे वे अभी तक नहीं संभाल पाये हैं। वे अभी हरियाणा प्रभारी पद से मुक्त नहीं किये गये हैं।

दिल्ली के पीसीसी अध्यक्ष देवेन्द्र यादव पंजाब के प्रभारी भी हैं। यह स्थिति हर तरह से बेमेल ही मानी जायेगी। इससे भी ऊपर एक बात और वे दिल्ली विधानसभा चुनाव भी लड़ रहे हैं तथा पप्पू यादव आज उनके चुनाव क्षेत्र में प्रचार करने भी आये थे।

भँवर जितेन्द्र सिंह, जो दो राज्यों- मध्य प्रदेश एवं असम, के प्रभारी हैं, ने पार्टी नेतृत्व को पत्र लिखा है कि वे मध्य प्रदेश का प्रभार छोड़ना तथा असम के प्रभारी बने रहना चाहते हैं। उनके नेतृत्व में, कांग्रेस की ओडिशा में जबरदस्त हार

( शेष पृष्ठ 3 पर )

## गौतम अडानी ने महाकुंभ में पूजा की

प्रयागराज, 21 जनवरी। महाकुंभ में अडाणी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडाणी ने संगम पर पूजा-अर्चना की और प्रसिद्ध बड़े हनुमान जी के मंदिर में दर्शन किए। संगम में पूजा करने के बाद मीडिया से बात करते हुए गौतम अडाणी ने कहा कि प्रयागराज महाकुंभ में मुझे जो अनुभव हुआ, वो अद्भुत है। यहां के प्रबंधन के लिए मैं देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी

- इस्कॉन के साथ अडानी समूह महाकुंभ में रोज एक लाख श्रद्धालुओं को महा प्रसाद का वितरण कर रहा है।

आदित्यनाथ को धन्यवाद देना चाहता हूं। यहां जो प्रबंधन है- वो प्रबंधन संस्थानों के लिए शोध का विषय है। मेरे लिए मां गंगा के आशीर्वाद से बढ़ कर कुछ नहीं है। गौतम अडाणी ने आगे कहा कि उत्तर प्रदेश में अवसर बहुत ज्यादा हैं, राज्य के विकास में अडाणी ग्रुप का महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अडानी इस्कॉन पंडाल में आयोजित भंडारा सेवा में भी शामिल हुए।

( शेष पृष्ठ 3 पर )

## कोलकाता रेप-मर्डर केस, सीजेआई आज करेंगे सुनवाई

### सुप्रीम कोर्ट में जाँच की खामियों को लेकर दर्ज याचिका में मृतक जूनियर डॉक्टर के माता-पिता भी पार्टी हैं

- मृतक जूनियर डॉक्टर के पिता ने 42 सवालों, जिनके उन्हें जवाब नहीं मिले हैं, की लिस्ट लेकर सुप्रीम कोर्ट में दस्तक दी है। ऐसी संभावना है कि सुप्रीम कोर्ट केस को रीओपन कर सकता है।
- मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सियालदह सिटी कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी, उन्होंने आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग की।
- वहीं, मृतका के परिजनों व कई अन्य का कहना है कि इस जाँच में कई बड़े लोगों को बचाया गया है।
- कानून विशेषज्ञों का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के साथ समूचा केस नया मोड़ ले सकता है।

-अंजन रॉय-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जनवरी। आर.जी. कर मैडिकल कॉलेज एण्ड हॉस्पीटल में जूनियर डॉक्टर के दुष्कर्म और हत्या का मामला दिन पर दिन और ज्यादा जिज्ञासा का मसला बन रहा है।

कोलकाता के सिटी कोर्ट ने मुख्य आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी है और अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बैंच में बुधवार को केस की सुनवाई होगी जिसमें जांच के नतीजों की समीक्षा की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट में दर्ज याचिका में मृतक डॉक्टर के माता-पिता भी पार्टी हैं।

सुप्रीम कोर्ट जांच की खामियों और दोषों की जानकारी दी गई है संभावना है कि मामले को फिर खोला जाएगा ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या इस अपराध में अन्य लोग भी शामिल थे।

सियालदह सिटी कोर्ट के फैसले को राज्य सरकार ने भी हाईकोर्ट में चुनौती दी है जिस पर बुधवार को सुनवाई होगी।

राज्य राजनैतिक दल भी इस पूरे फैसले तथा घटनाक्रम जो मोड ले रहे हैं उस पर काफी सक्रिय हैं। जिसकी भाजपा राज्य सरकार हर साजिश में शामिल होने तथा सबूत नष्ट करने का आरोप लगा रही है और सत्तारूढ पार्टी यह साबित करने में रात दिन एक कर रही है कि आरोपी को सजा दिलाने के लिए वह कितनी गंभीर है।

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले दिन से ही आरोपी को फांसी की सजा देने की मांग कर रही है और अब सियालदह कोर्ट के फैसले के बाद उन्होंने आरोपी संजय रॉय को फांसी देने की मांग पर ज्यादा शोर मचाना शुरू कर दिया है।

कानूनविद मानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की हाई पावर बैंच के समक्ष रेप व मर्डर का यह मामले आने से समूचे केस ने नया मोड़ ले लिया है सबसे महत्वपूर्ण बात है राज्य पुलिस के आचरण व्यवहार पर सवाल उठ रहे हैं।

सियालदह कोर्ट के 132 पृष्ठ के फैसले में पुलिस के आचरण पर आरोप

( शेष पृष्ठ 3 पर )

## संकल्प पत्र-2 में भाजपा ने विद्यार्थियों व कामगारों के लिये घोषणायें कीं

नयी दिल्ली, 21 जनवरी। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र का दूसरा हिस्सा जारी

- जरुरतमंद बच्चों को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा दी जायेगी।

किया। विकसित दिल्ली संकल्प पत्र - 2 को पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने जारी किया। इस मौके पर उन्होंने दिल्ली में सत्तारूढ़ आम आदमी पार्टी के घोटालों की जांच कराने की बात कहते हुए कहा, हम जो कहते हैं, वो करके दिखाते हैं। मोदी की गारंटी है कि दिल्ली में हर गारंटी पूरी होगी।

भाजपा ने अपने संकल्प पत्र-2 में विद्यार्थियों के लिए एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि दिल्ली में जरूरतमंदों के बच्चों को केजी से पीजी

( शेष पृष्ठ 3 पर )

## 'केवल अमेरिका में पैदा होना, किसी शिशु को अमेरिकी नागरिक होने का अधिकार नहीं देगा'

### राष्ट्रपति ट्रम्प ने अमेरिका में "बर्थ टूरिज़्म" खत्म करने का आदेश पारित किया

- "अगर किसी शिशु के माता-पिता में से एक अमेरिका का नागरिक नहीं है और वह दम्पती अस्थाई "वर्क परमिट" लेकर अमेरिका में रह रहा है या टूरिस्ट वीज़ा पर अमेरिका आया है, तो उनकी संतान को स्वमेव अमेरिका की नागरिकता नहीं मिलेगी।
- अमेरिका में 54 लाख भारतीय हैं, जिसमें से 2/3 इमिग्रैंट्स (अप्रवासी) हैं तथा 34 प्रतिशत अमेरिका में जन्मे हैं।

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 21 जनवरी। अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने और वाइट हाउस लौटने के साथ ही ट्रम्प ने बिना वक्त गंवाए अमेरिका को पुनः महान बनाने के अपने चुनावी वादे को पूरा करने और मौजूदा व्यवस्था को अस्थिर करने की "डिसरप्शन" योजना शुरु कर दी है।

वॉशिंगटन डी.सी. में कैपिटल हिल से दिए गए भाषण में ट्रम्प के समर्थकों ने उस समय भारी उत्साह दर्शाया, जब ट्रम्प ने कहा, अब से अमेरिका की अधिकारिक नीति में दो ही जैंडर होंगे "मेल और फीमेल।" ट्रम्प ने शपथ ली कि जाति और लिंग को सार्वजनिक एवं निजी जीवन के हर पहलू में "सोशल इंजीनियरिंग" के प्रयासों को हटाया जाएगा।

उन्होंने ऐसा देश बनाने की घोषणा की, जो "कलर ब्लाइंड" और मैरिट पर आधारित होगा।

पनामा नहर को वापस लेने की घोषणा की, साथ-साथ इन्फ्लेशन के लिए सरकार के बढ़ते खर्च को जिम्मेदार ठहराने तक ट्रम्प के भाषण में कई बड़े-बड़े दावे और घोषणाएं की गईं, इसके बाद कई एग्ज़ीक्युटिव ऑर्डर्स पारित हुए।

अपने उद्घाटन भाषण में ट्रम्प का अंदाज़ बेहद उग्र था, उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडन की काफी आलोचना की।

उन्होंने कहा कि वे सरकार के "वेपनाइज़ेशन" के पीड़ित थे, उन्होंने सरकार को उग्र व भ्रष्ट संस्थान बताया।

ट्रम्प ने कहा, मेरा चुनाव भयानक विश्वासघात को पलटने के लिए था, आज से अमेरिका के पतन के दिन खत्म हुए।

अपने भाषण में कहा, इस समय पनामा शहर पर चीन का कब्जा है। अमेरिका का एमरजैंसी रैस्पॉन्स सिस्टम टूट चुका है और विदेशों की जेलों और मानसिक संस्थानों से आए लोगों को अमेरिका में शरण दी जा रही है।

ट्रम्प ने अपने कार्यकाल की शुरुआत कई कार्यकारी आदेशों से की, जिनमें ऊर्जा, इमिग्रेशन अपराध की माफी जैसी घोषनाएं थीं

ट्रम्प ने उन 1500 लोगों का माफी दे दी, जो 2021 में अमेरिका के कैपिटल हिल में घुसे थे। उन्होंने, मैक्सिको सीमा पर आपातकाल लगाया।

दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी वैश्विक व्यवस्था को करारा झटका देते हुए ट्रम्प ने अमेरिका को पैरिस क्लाइमेट डील और वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गनाइज़ेशन से अलग कर दिया।

उन्होंने अपराधी गुटों को आतंकी संगठन करार देने की घोषणा की।

अमेरिकन परम्परा को एक और झटका देते हुए ट्रम्प ने गैर स्थायी निवासियों के बच्चों को जन्म के आधार पर अमेरिका की नागरिकता मिलने के अधिकार को खत्म कर दिया। यह फैसला अमेरिका में स्थायी वीज़ा पर रहने वाले लाखों भारतीय को प्रभावित कर सकता है।

यह निर्णय 30 दिन में प्रभावी हो सकता है, पर इसे कानूनी चुनौती दी जा सकती है। न्यू हैम्पशायर के इमिग्रेशन वकीलों ने इस आदेश के खिलाफ केस भी दायर कर दिया है।

जन्मसिद्ध नागरिकता वह कानूनी सिद्धांत है, जिसके आधार पर बच्चों को इस देश की नागरिकता मिलती है, जहाँ वे जन्म लेते है, भले ही उनके माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हों।

अमेरिका के संविधान में हुए 14वें संशोधन, जो 1868 में हुआ था, के तहत यह सिद्धांत लागू किया गया था। इसका उद्देश्य था गुलामी से मुक्ति पाने वालों की स्थिति स्पष्ट करना। इसके तहत अमेरिका में जन्म लेने वाले सभी

( शेष पृष्ठ 3 पर )

## सैफ 5 दिन बाद अस्पताल से घर पहुंचे

मुंबई, 21 जनवरी। बॉलीवुड अभिनेता सैफ अली खान, जो बांद्रा स्थित अपने घर पर चोरी के प्रयास में किए गए हमले में गंभीर रूप से घायल हो गए थे, को पांच दिन बाद मंगलवार को मुंबई के लीलावती अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। इस मौके पर अभिनेता की मां एवं पूर्व अभिनेत्री शर्मिला टैगोर उनके साथ थीं। सैफ की पत्नी और अभिनेत्री करीना कपूर खान अस्पताल

- संक्रमण से बचने के लिये उन्हें एक सप्ताह आगंतुकों से नहीं मिलने की सलाह दी गई है।

में मौजूद थीं लेकिन कुछ देर पहले घर के लिए रवाना हो गईं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, सैफ को किसी भी संक्रमण से बचने के लिए एक सप्ताह तक पूरी तरह आराम करने और आगंतुकों से न मिलने की सलाह दी गई है। अस्पताल के साथ-साथ खान के आवास पर भी भारी पुलिस तैनाती

( शेष पृष्ठ 3 पर )